648. *[Transferred to 4th March,* 1994]

बिहार को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

649. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से बिहार को आवंटित की जा रही आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, चावल, गेहूं, खाद्य तेल और चीनी की मात्रा स्थिर रही है;

(ख) क्या राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में उक्त वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि किया जाना अपेक्षित नहीं है;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार बिहार को अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं आवंटित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कमालुद्दीन अहमद: (क) से (ङ). वर्ष 1991, और 1992 और 1993 में बिहार सरकार को चावल, गेहूं लेवी चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल का आवंटन निम्नवत है:

(हजार मी०टन में)

वस्तुएं	1991	1992	1993
गेहूं	561.30	617.36	725.16
चावल	131.00	247.06	305.16
लेवी चीनी	419.96	431.64	431.64
खाद्य तेल	5.50	4.50	0.36
मिट्टी का तेल	468.26	469.32	495.20

राज्य सरकारों और संघ राज्य श्रेत्र प्रशासनों, जिनमें बिहार शामिल है, को आवश्यक वस्तुओं का आवटन, केन्द्रीय पूल में भण्डार, की गई वसूली, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं और मौसमी कारणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते है और इनका प्रयोजन किसी राज्य की समस्त आवश्कताओं को पूरा करना नहीं होता है। सरकार द्वारा आवंटन करते समय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें बिहार शामिल है, की वास्तविक की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। बिहार को खाद्यान्नों का आवंटन करने के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

650. *[Transferred to 4th March,* 1994].

651. *[Transferred to 4th March,* 1994].

Public utility services and the development of the awareness of consumer rights

652. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minsitcr of CIVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether a citizens charter is proposed to be drawn up for raising the standard of public utility services and consumer awareness of their rights;

(b) if so, the steps taken and being taken in that direction; and

(c) which areas of public utility Services are sought to be covered thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c). A proposal for drawing up a "Citizen's Charter" was discussed in the 15th meeting of the Central Consumer Protection Council held on 25th January, 1994. As per the Council's recommendations a Working Group to work out details of the proposal, particularly reagarding medical services has been constituted.